(c) whether special steps are being taken by Government to set-up more industries in Assam by private participation;

(d) if so, the comprehensive plan thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) As per available information 2 Industrial Licences were granted and 8 Industrial Enterpreneures Memoranda (IEMs) were implemented in private sector other than Small Scale Industries in the State of Assam during the post liberalisation period i.e. (August, 1991 to December, 1998).

(b) During the above period, proposals amounting to Rs. 1,81,296.54 Crores of foreign investment including NRIs were approved, State-wise break-up is given in the "Statement" *(See* below)

(c) to (e) The State of Assam has been allotted three Growth Centres which would be endowed with infrastructural facilities to attract Industries. Besides, under the Transport Subsidy Scheme an amount of Rs. 171.70 crores has been released by the Central Government in fabour of the units located in Assam. However, after liberalisation, most of the industries are delicensed and enterpreneurs are free to set up industries by filing an IEM. Private investment is mainly dependent on the proactive measures undertaken in each state and its relative attractiveness as an investment destination.

Statement

State-wise break up of foreign investment made including NRI proposals in the country during the period from August 1991 to December 1998.

Sl. No.	Name of the State/UTs	Amount approved (Rs. in crores)
1.	Andhra Pradesh	7904.03
2.	Assam	1.5
3.	Bihar	227.47
4.	Gujarat	9968.31
5.	Haryana	2207.34
6.	Himachal Pradesh	344.16
7.	Jammu and Kashmir	8.01
8.	Karnataka	15306.91
9.	Kerala	597.75
10.	Madhya Pradesh	7640.43
11.	Maharashtra	22215.79
12.	Manipur	3.19
13.	Meghalaya	52.96
14.	Nagaland	3.68
15.	Orissa	7763.10
16.	Punjab	1907.18
17.	Rajasthan	2246.28
18.	Tamil Nadu	12412.55
19.	Tripura	.68
20.	Uttar Pradesh	3035.83
21.	West Bengal	7378.92
22.	Andaman and Nicobar	13.79
23.	Arunachal Pradesh	11.06
24.	Chandigarh	[illegible].00
25	Dadra and Nagar Haveli	88.03
26.	Delhi	23632.25
27.	Goa	468.41
28.	Lakshadweep	0.50
29.	Pondicherry	353.54
30.	Daman and Diu	20.30
31.	Others	57344.59
	TOTAL	181296.54

Threat to MUL

2984. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Maruti Udyog Ltd. is facing any threat due to boom in car industry;

(b) if so, the details in this regard;

(c) if not, whether prices of Maruti cars have been decreased recently to capture more car market; and

(d) the likely impact on Maruti Udyog Ltd. of this decrease in prices of cars?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): (a) to (d) As per Maruti Udyog Limited (MUL), due to recessionary condition in the market in the third quarter of 1998-99,

there was a decline in demand for passenger cars, MUL undertook a series of measures including price re-adjustments to stimulate the demand. Due to this, the fourth quarter has seen a growth of 43% over the third quarter in the sales.

राज्यों के औद्योगिक कार्यकरण की समीक्षा

2985. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राज्यों की औद्योगिक क्षमता और औद्योगिक कार्य-प्रणाली की समीक्षा की है ताकि देश के औद्योगिक विकास के प्रतिशत का आकलन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या आकलन के अनुसार औद्योगिक उत्पादन की प्रतिशतता को निराशाजनक और नकारात्मक पाया गया है;

(ग) उसके कारणों सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक देशभर में सभी राज्यों में फैले हुए औद्योगिक एककों द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणियों के आधार पर तैयार किया जाता है। औद्योगिक विकास का मूल्यांकन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, औद्योगिक विकास अप्रैल-फरवरी, 1997-98 के दौरान 4.9% की तुलना में अप्रैल-फरवरी, 1998-99 के दौरान 3.9% है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार कार्य निष्पादन के एक विश्लेषण से यह पता चलता है कि अप्रैल-फरवरी, 1999 के दौरान कुल 17 द्विअंकीय उद्योग समूहों में से 11 में सकारात्मक विकास दरें प्राप्त हुई हैं जबकि 6 उद्योग समूहों ने नकारात्मक विकास दर्शाया है।

(ग) औद्योगिक विकास में धीमेपन के लिए घरेलू और बाहरी दोनों कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

— घरेलू कारकों में, सामान्य निवेश में कमी के कारण कमजोर मांग शामिल है, जिसका मुख्य कारण पूंजी बाजार में मंदी की स्थितियां थी।

— बाहरी पक्ष की दृष्टि से विश्व निर्यात विकास धीमा रहा है। जिससे भारत के निर्यात विकास पर प्रभाव पड़ा है। चूंकि निर्यात संबंधी उत्पादन औद्योगिक उत्पादन का एक बड़ा भाग होता है इसलिए इससे औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

— पूर्वी एशिया और ब्राजील में मुद्राओं के अवमूल्यन के कारण भारतीय कंपनियां सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा की वजह से भी प्रभावित हुई हैं।

(घ) सरकार ने त्वरित विकास को अधिप्रेरित करने के लिए अनेक उपाय घोषित किये हैं। ये इस प्रकार हैं:—

(1) यू०एस०सी०आर०ए० को रद्द करना और गृह स्वामित्व संबंधी प्रोत्साहन।

(2) सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने और पूंजी बाजार को पुनरुज्जीवित करने के लिए शेयरों की पुनः खरीद व अंतःकारपोरेट ऋणों की अनुमति दी है।

1999-2000 के बजट में, तेजी से औद्योगिक विकास करने के लिए उद्योगों के पुनरुज्जीवन हेतु विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। जो इस प्रकार है:—

(1) एकाधिकार तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम को बदलने के लिए नये प्रतियोगी कानून।

(2) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन की सूची को बढ़ाया जायेगा ताकि महत्वपूर्ण उद्योग एवं सेवा क्षेत्र इसमें शामिल किए जा सकें।

(3) उद्योग मंत्रालय के भीतर ही एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण गठित करने की घोषणा की गई है ताकि निवेश अंतः-प्रवाह में तेजी और परियोजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हो सके।

(4) उत्पादन शुल्क दर में आमूल-चूल परिवर्तन मौजूदा 11 दरों को घटाकर केवल 3 दरें कर दिया गया है।

(5) 100% मोडवेट ऋण को बनाये रखना।

(6) सीमा शुल्क की मूल्यानुसार 7 प्रमुख दरों को घटाकर 5 मूल दरें की गई हैं।